

अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को सरकार त्वरित नकदी उपलब्ध कराएगी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता ने श्रीनिवार को द हिंदू को बताया कि केंद्र सरकार ने अमेरिका द्वारा टैरिफ वृद्धि का जवाब देने के लिए एक "कार्य योजना" तैयार की है, जिसमें अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य न केवल अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाना है।

सूरों के अनुसार, अल्पकालिक उपायों में निर्यातकों को तकाल नकदी और अनुपालन संबंधी राहत प्रदान करना और उन्हें कमज़ोर क्षेत्रों में ऑडर स्तर और रोज़गार बनाए रखने में मदद करना शामिल है।

प्रवक्ता ने कहा, "भारत सरकार समय पर, सुनियोजित और व्यापक बहुस्तरीय राजनीति के साथ सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे रही है, जो न केवल भारतीय निर्यातकों की सुरक्षा के लिए, बल्कि वैश्विक बाज़ारों में हमारी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए भी डिजाइन की गई है।"

"वाणिज्य विभाग ने इस टैरिफ वृद्धि का जवाब देने के लिए एक अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की है।"

मार्गदर्शक सिद्धांत
मंत्रालय के सूरों के अनुसार, यह कार्य योजना कुछ "मार्गदर्शक सिद्धांतों" पर आधारित है: निर्यातकों को तरलता, अनुपालन और ऑडर स्तर के संबंध में तकाल राहत प्रदान करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाना, मौजूदा व्यापार समझौतों का लाप उठाना और निर्यातकों को अन्य गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना।

एक सूरों ने कहा, "यह अनुमान है कि टैरिफ के झटके के कारण निर्यातकों को भुगतान में देरी, प्राप्त चक्र में देरी और ऑडर रद्द होने का समान करना पड़ सकता है।"

भारत, चीन सीमा मुद्दे के निष्पक्ष समाधान के लिए प्रतिबद्ध: मोदी

प्रधानमंत्री की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह सीमा पर 'उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य' समाधान के लिए तैयार हैं; शी ने कहा कि सीमा संबंधी मुद्दों को परिभाषित नहीं करना चाहिए; विदेश सचिव ने कहा कि भारत, चीन की अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार को स्थिर कर सकती हैं।

Vighnesh P. Venkitesh
TIANJIN

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया।

उत्तरी चीनी शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतने हुई बैठक में, दोनों नेताओं ने सीधी उड़ानों और वीजा सुविधा के माध्यम से लोगों

के बीच संबंधों को मजबूत करने की आरक्षकता पर सहमति व्यक्त की, साथ ही कैलाश

मानसरोवर यात्रा और पर्सटक वीजा की बहाली की भी बढ़ावा दिया, जिससे दोनों पड़ोसियों के

बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। श्री शी ने कहा कि सीमा मुद्दे को

समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए।



बहतर होते संबंध: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान एक बैठक के दौरान। धीरेंद्र अग्रवाल

वैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "दोनों नेताओं ने पिछले साल सफलतापूर्वक सैनिकों की वापसी और उसके बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।"

विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने रविवार रात एक प्रेस वार्ता में कहा कि श्री मोदी ने आतंकवाद से निपटने में आपसी सहयोग का आहान किया।

CONTINUED ON
» PAGE 10

मोदी ने शी जिनपिंग से कहा, दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं।

Suhasini Haidar

NEW DELHI

इस मुद्दे पर नई दिल्ली के हालिया रुख में बदलाव लाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि दोनों देश आतंकवाद के "पीड़ित" हैं और उन्हें इस "संकट" से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पहलगाम हमलों का मुद्दा उठाया, विदेश सचिव ने कहा कि बैठक में इस पर चर्चा हुई।

CONTINUED ON
» PAGE 10

Calm waters



मूर्ति को विदाइ: रविवार को श्रीनगर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर झोलम नदी में विसर्जन के लिए नाव पर गणेश की मूर्ति ले जाते कश्मीरी पंडित। इमरान निसार

बिहार में 33,000 से अधिक मतदाता मतदाता सूची में पुनः नाम शामिल कराना चाहते हैं

The Hindu Bureau
NEW DELHI

बिहार में मतदाता सूची के विशेष ग्रन्त पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए केवल एक दिन शेष रहते हुए, चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि 33,326 लोगों ने मतदाता सूची में पुनः शामिल होने के लिए आवेदन किया है।

1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 7,24 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे, जो चुनावी राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रकाशित मतदाता सूची की तुलना में 65 लाख कम नाम हैं।

चुनाव आयोग 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा।

FULL REPORT ON
» PAGE 11

'छोटे बादल फटने' की घटनाएं बढ़ रही हैं: आईएमडी प्रमुख

Jacob Koshy
NEW DELHI

हाल के वर्षों में भारत में बादल फटने की घटनाओं में कोई बढ़ती प्रवृत्ति नहीं देखी गई है और इनका पूर्वानुमान लगाना "असंभव" बना हुआ है। हालाँकि, 'छोटे बादल फटने' की घटनाओं में वृद्धि हुई है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युजय महापात्र ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में कहा।

उन्होंने कहा कि सितंबर में - जो कि आखिरी आधिकारिक मानसून महीना है - पिछले महीनों की तरह, "सामान्य से अधिक" या सामान्य औसत 16.7 सेमी से 9% अधिक बारिश होने की उम्मीद है।

पूर्वोत्तर राज्यों और "अंतर्यामी" दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में छोड़कर, देश के बाकी हिस्सों में

उत्तर-पश्चिम भारत में

मानसून के महीनों में

सामान्य से 26% अधिक

वर्षा हुई

सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है।

अब तक मानसून के तीन महीनों में "सामान्य से अधिक" वर्षा हुई है, जो मई में आईएमडी के पूर्वीनुगमन के अनुरूप है। 1 जून से 31 अगस्त के दौरान हुई वर्षा इन तीन महीनों के अनुरूप है। 1 जून से 31 अगस्त के दौरान हुई वर्षा इन तीन महीनों के अनुरूप है।

उन्होंने कहा कि सितंबर में - जो कि आखिरी आधिकारिक मानसून महीना है - पिछले महीनों की तरह, "सामान्य से अधिक" या सामान्य औसत 16.7 सेमी से 9% अधिक बारिश होने की उम्मीद है।

पूर्वोत्तर राज्यों और "अंतर्यामी" दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में

पूर्व में कम बारिश मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से क्रमशः 8.6% और 9.3%

अधिक वर्षा हुई, जबकि केवल पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में - जहाँ

मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है - सामान्य से 17% कम वर्षा हुई। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर भारत में अगस्त में 26.5 सेमी वर्षा हुई, जो 2001 के बाद से सबसे अधिक थी। दक्षिणी प्रायद्वीप में 25 सेमी बारिश 2001 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा थी।

अगस्त 2025 में भारी बारिश (एक दिन में 20 सेमी या उससे ज्यादा) के

700 से ज्यादा मामले सामने आए, जो 2021 के बाद से दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है, जबकि 2024 में 800 से ज्यादा बारिश हुई थी।

उत्तर भारत में अत्यधिक सक्रिय मानसून - जिसमें उत्तराखण्ड में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान देखा जाता है - कर्ड पश्चिमी विक्षेपों (भूमध्य सागर भूमध्य सागर से भारत आने वाले तूफान) और बंग

तेलंगाना में पिछड़ी जातियों के लिए 42% कौटा लागू करने संबंधी विधेयक पारित इसी आशय के दो विधेयक और एक अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को दो विधेयक पारित करके स्थानीय निकायों के चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42% आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रसरण कर दिया; तेलंगाना नगरपालिका (त्रुटीय संशोधन) विधेयक, 2025, और तेलंगाना पंचायत राज (त्रुटीय संशोधन) अधिनियम, 2025।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इसी आशय के दो विधेयक और एक अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने नगरपालिका संशोधन विधेयक और पंचायत राज मंत्री दानसरी अनसूया सीधकका ने पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश किया।

श्रीधर बाबू ने कहा कि अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में है, जबकि पिछड़े वर्गों के लिए कोटा इस शर्त के अधीन है कि एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

सरकार ने राज्य के सभी परिवारों से वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त करने के लिए समाजिक-आर्थिक, शिक्षा, गोपनीयता और जातिगत सर्वेक्षण कराया था।

विषय ने उठाए सवाल

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भाजपा ने सवाल उठाए कि सरकार ऐसे समय में आरक्षण कैसे लागू करने की योजना बना रही है जब केंद्र ने अभी तक पिछले विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी है।

बीआरएस सदस्य जी. कमलाकर ने कहा कि बीआरएस पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने कानूनी बाधाओं को लेकर चिता जताई। उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का उदाहरण दिया जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में इसी तरह के विधेयक पारित नहीं हो सके।

भाजपा नेता पायल शंकर ने कहा कि पार्टी विधेयकों के समर्थन में है, लेकिन स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाँच वर्षों में पिछड़ी जातियों के लिए ₹1 लाख करोड़ के बजटीय आवंटन का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।



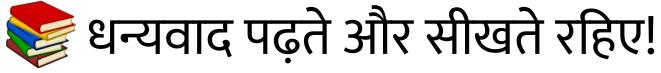
प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

कृपया इस वेबसाइट <https://epapers.netlify.app/> को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

लक्ष्य: जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!



धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

भारत के युवाओं को पंख देना

भारत की विकास गत्थ हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री ने देश में भारत की आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने वैश्विक परिवर्ष में अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है, और इस यात्रा में इसके मानव संसाधन की शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इस सफलता की कहानी को बल इस तथ्य से मिलता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। RBI-KLEMS के अनुसार, जहाँ 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ नौकरियाँ सृजित हुईं, वहीं उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियाँ सृजित हुईं। EPFO के अंकड़ों के अनुसार, औपचारिकीकरण में भी तेजी आई है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

हालांकि, वास्तविक परिवर्तन सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हुआ है। 2015 में, केवल 19% भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना की अंतर्गत आते थे। 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 64.3% हो गई है, यानी 94 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचकर, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज विस्तार में से एक माना है।

आगे देखते हुए, यह स्पष्ट है कि देश का भविष्य न केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, हमारे द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा और हमारे युवाओं की प्रगति के लिए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, कृतिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित अनिश्चितताओं, आपूर्ति-शृखला में बदलावों और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली अन्य कमज़ोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर खड़ा है।

भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जबकि पश्चिमी देशों में वृद्धि आबादी देखी जा रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश - इसकी युवा शक्ति - को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। पिछे भी, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। 2047 तक विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ते हुए, हमारे सामने चुनौती स्पष्ट है: हमें 'संभावना' से समृद्धि की ओर बढ़ना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, रोजगार अब केवल एक आर्थिक संकेतन नहीं है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें वैश्विक साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल से सुरक्षित रहें। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है।

एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम

इस चूनीती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच की खाई को पाटने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू की है। शुरूआत में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित और प्रधानमंत्री द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित, यह योजना पैमाने और डिजाइन, दोनों ही दृष्टि से अंतीम से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रातिनिधित्व करती है। ₹1 लाख करोड़ के परिवर्य के साथ, यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक आबादी देखी जा रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश - इसकी युवा शक्ति - को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। पिछे भी, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। 2047 तक विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ते हुए, हमारे सामने चुनौती स्पष्ट है: हमें 'संभावना' से समृद्धि की ओर बढ़ना होगा।

इस योजना को इसकी संरचना ही विशेष बनाती है। रोजगार सूजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के परिपर्वत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उदयम प्रतिस्पर्धात्मकता की दोहरी चूनीती का एक साथ समाधान करती है। भाग A के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दो किश्तों में ₹15,000 तक) और भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं (प्रति माह प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 तक) दोनों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें, यह योजना कर्मचारियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करती है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करती है।

योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में स्पष्ट प्रयास भी उत्तरा है। लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए श्रमिकों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, यह योजना कर्मचारियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करती है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करती है।

योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में स्पष्ट प्रयास भी उत्तरा है। यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें वैश्विक साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल से सुरक्षित रहें। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है।

श्रमिकों और नियोक्ताओं का समर्थन करके, यह योजना यह मानती है कि रोजगार सूजन एक साझा जिम्मेदारी है। चूंकि भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे। यहाँ तक कि सबसे छोटे उद्यम और कार्यवल में शमिल होने वाले नए व्यक्ति को भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में शामिल किया गया है।

एक नया भारत

यह योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं बढ़कर है। यह पहल जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह विकसित भारत के साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहाँ हर युवा को सार्थक रोजगार प्रदान किए जाएंगे, रोजगार अपने अवसर के लिए रोजगार, अपने व्यवसाय के लिए रोजगार, अपने अवसरिक अर्थों में रोजगार निर्माण है। इस पहल के साथ, मोटी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं

श्रमिकों और नियोक्ताओं का समर्थन करके, यह योजना यह मानती है कि रोजगार सूजन एक साझा जिम्मेदारी है। चूंकि भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे। यहाँ तक कि सबसे छोटे उद्यम और कार्यवल में शमिल होने वाले नए व्यक्ति को भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में शामिल किया गया है।

कई बाधाएँ

यह योजना के लिए ज़रूरी है कि विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ते हुए, हमारे सामने चुनौती स्पष्ट है: हमें 'संभावना' से समृद्धि की ओर बढ़ना होगा।

रायपुर की किताब से एक पता लेना

अब समय या गया है कि भारत के सभी प्रमुख शहरों में पुलिस कमिश्री प्रणाली अपनाई जाए।

स्वतंत्रा दिवस पर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि कानून-व्यवस्था की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए रायपुर में जल्द ही पुलिस कमिश्री प्रणाली लागू की जाएगी। रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला शहर होगा जहाँ यह प्रणाली लागू होगी। लगभग 15 वर्ष पूर्व (2011 की जनगणना के अनुसार) रायपुर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी।

पुलिस कमिश्री प्रणाली अनिवार्य रूप से आदेश और नियंत्रण की एक श्रृंखला है। इसके दो मूल कार्य निर्णय तेना और उन्हें लागू करना हैं। इस प्राणी में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ कुछ कार्यों के लिए एक निश्चित पद के पुलिस अधिकारियों में विद्वित होती हैं। इससे पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच साझा जिम्मेदारी वाले कुछ कार्यवलों, विशेष रूप से अपराधिक विवरण के लिए एक नियंत्रण के लिए अंतर समाप्त होता है।

पुलिस कमिश्री प्रणाली अनिवार्य रूप से आदेश और नियंत्रण की एक श्रृंखला है। इसी प्राणी के तहत राज्यों को दी गई पुलिस कमिश्री के अनुसार लागू होने के बाद से यह कानून बदल गया है। वीएनएसएस ने यह अनिवार्य शर्त हटा दी है कि किसी शहर का बदल गया है। वीएनएसएस ने यह अनिवार्य शर्त हटा दी है कि किसी शहर का बदल गया है। तभी विकसित विवरण के लिए एक वैश्विक विवरण की शक्तियाँ विष्णु देव की ओर बढ़ना होती हैं। वीएनएसएस के लिए एक वैश्विक विवरण की शक्तियाँ विष्णु देव की ओर बढ़ना होती हैं। वीएनएसएस के लिए एक वैश्विक विवरण की शक्तियाँ विष्णु देव की ओर बढ़ना होती हैं।

पुलिस कमिश्री प्रणाली विष्णु देव का लागू होने तक, सीआरपीसी के तहत अनिवार्य शर्त यह थी कि केवल

Text & Context

THE HINDU

भारत के संघीय ढांचे का महत्व

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान में राज्यों के निर्माण की क्या प्रक्रियाएँ हैं?
राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है? क्या जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं?

EXPLAINER

C. B. P. Srivastava

अब तक की कहानी: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के महत्व को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष अद्यतन ने सभी कहा कि उसके पास सभी विशेषज्ञान नहीं हैं और सरकार को कुछ निर्णय लेने हैं। अदालत, जरूर अहमद भट बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश मामले में दायर याचिका पर सुनवाइ कर रही है। तक दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल न करने के बाहे के नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस संदर्भ में एक और तर्क यह है कि इससे सघवाद की आवश्यक विशेषताओं और इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन हो रहा है।

राज्यों का निर्माण कैसे होता है?

भारत के संविधान में राज्यों के निर्माण के लिए तीन प्रक्रियाएँ निहित हैं - प्रवेश, स्थापना और निर्माण। भारत के क्षेत्र में किसी नए राज्य के प्रवेश के लिए, उस इकाई की अपनी संगठित राजनीतिक इकाई होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि अधिग्रहण के माध्यम से प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्दिष्ट हो। यह वह प्रक्रिया थी जिसके तहत 1947 में जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। भारतीय स्वतंत्रा अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत इस पत्र को निर्वाचित करके, कश्मीर के तकालीन शासक, महाराजा हारि सिंह ने अपने राज्य को भारत में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की थी।

एक नए राज्य की स्थापना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिग्रहण की परिभाषा के अनुसार क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाए। भारत ने गोवा और सिक्किम का अधिग्रहण किया और उन्हें राज्यों के रूप में स्थापित किया।

एक नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, वास्तव में, एक मौजूदा राज्य का पुनर्गठन ही है, जिसके कारण भारत ने 1956 में अपने 14 राज्यों की संख्या को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियम से पहले 29 राज्यों तक बढ़ा दिया।



महासंघ के लिए: कांग्रेस कार्यकर्ता 20 जुलाई को जम्मू में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग को लेकर विरोध मार्च में भाग लेते हुए। पीटीआई

संविधान का अनुच्छेद 3 पुनर्गठन की इस प्रक्रिया का प्रावधान करता है जिसके तहत संसद का नया बनाकर किसी राज्य के भू-भाग को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी भू-भाग को किसी राज्य के भू-भाग के मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है; किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है; किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है; किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है; या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। हालांकि, संघ किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम तो कर सकता है, लेकिन उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उससे कुछ नहीं छीन सकता। यह भारत की संघीय संरचना के विरुद्ध कदम होगा। इसलिए, केंद्र के लिए जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2024 में हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित राज्य का दर्जा बहाल किया जाए।

भारत के संघीय ढांचे के बारे में क्या?

भारत की राज्यों का संघ बनाया गया है जिसका अर्थ है कि यह अविभाज्य है और राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 के इस प्रविधान की व्याख्या द्वारा अर्थ में कि जो सकती है कि इंडिया शब्द एकात्मक संघ को दर्शाता है, जबकि "भारत" शब्द एक संस्कृतिक अर्थ रखता है कि भारत की एक मिश्रित संस्कृति है और विविधता में एकता विद्यमान है।

द्विसंसीय शासन प्रणाली होने के बावजूद, इसमें 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि 'संघ' स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस अनूठी विशेषता के पीछे का उद्देश्य भारत के संघीय चरित्र और एकात्मक भावना को सुनिश्चित करना है।

ओर्का मछलियाँ मनुष्यों को ताजा शिकार क्यों दे रही हैं?

क्या ये किलर ढेलें शिकार को छोड़ने या पुनः प्राप्त करने से पहले मानव प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही हैं?

Rohini Karandikar

अब तक की कहानी: कई ओर्का, जो डॉलिफ़न की सबसे बड़ी प्रजाति हैं और जिन्हें अक्सर किलर ढेल कहा जाता है, ताजा शिकार को इंसानों के साथ साझा करते पाए गए हैं। और वे सिफ़े अपना शिकार पेश नहीं करते, वे इसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। जर्नल ऑफ़ कम्प्लेक्ट एवं प्रॉजेक्ट एक्स्प्लोरेशन की अधिकारी ने अपने राज्यों को शामिल किया जाने की जांच की है कि ओर्का इसानों को भोजन क्यों दे रहे हैं।

टीम ने आँकड़े कैसे एकत्र किए?

हालांकि, उन्होंने जो सामग्रीय भागों से एकत्र किए: पूर्वी उत्तरी प्रशांत, पूर्वी उत्तरांचलीय प्रशांत, पश्चिमी दक्षिणी अटलांटिक और पूर्वी उत्तरी अटलांटिक। टीम ने अपने विशेषण में केवल उन्हीं उदाहरणों को शामिल किया जहां जानवरों के पास आने से पहले मानव पर्यवेक्षक ओर्का से काप़िया दीर्घी पर थे।

उदाहरण के लिए, पानी के नीचे भोजन के समय मनुष्यों के लिए मानदंड यह था कि वे किलर ढेल से संपर्क करने से पहले कम से कम 15 मीटर दूर रहें। तब जानवर अपनी शिकार की लंबाई के भीतर आ जाते और अपने शिकार को उनके शिकार के सामने छोड़ देते।

या ओर्का उद्धिमान होते हैं?

टीम जिन 34 मामलों को अंतिम रूप दे पाई, उनमें से 33 मामलों में ओर्का ने पेश किए गए शिकार को स्वीकार करने या छोड़ने से पहले मानव प्रतिक्रिया का इंतजार किया और पीछे दूर हो गया। उनके द्वारा पेश किए गए भोजन में समुद्री शैवाल, अक्षरशैली, मछली, सरीसूरी, पक्षी और स्तनधारी शामिल थे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें शुरू में इस प्रस्ताव की स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश कॉलंबिया, कनाडा में वे सेटोलंजी अनुसधान संस्थान के एक समुद्री जीवविज्ञानी, जेरेट टार्कस, उनमें से एक थे। "मैंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि जब यह हुआ तो मुझे साधा लगा," श्री टार्कस ने कहा।

ओर्का क्या कर रहे हैं?

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किलर ढेल शायद बस खेल रही होती है। हालांकि, यह गतिविधि आमतौर पर बच्चों से जुड़ी होती है, जबकि नए अध्ययन में पाया गया कि यह गतिविधि आमतौर पर बच्चों द्वारा किलर ढेल के बारे में इंसानों की जिजासा बढ़ा सकती है और संरक्षण प्रयासों से सुधार ला सकती है।

लेखकों ने कहा कि इन्हीं कारणों से, किलर ढेल खेल नहीं रही होंगी, बल्कि खोजबीन कर रही होंगी।

जानवर अपने भौतिक, सामाजिक और आपूर्वकालीय परिवेश के बारे में अनिश्चितता को कम करने के लिए अपने परिवेश का अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण तकनीकी रूप से ज्ञान की संवेदन खोज है और डॉलिफ़न की विकासित बढ़ावा और उत्तरांचलीय प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की वर्तमान स्थिति प्रभावित होती है। अगर इस पर सहमति हो जाती है, तो यह भारत की संवैधानिक संरचना के साथ असंगत होगा और निश्चित रूप से इसकी संघीय विशेषताओं को नष्ट कर देगा।

C. B. P. Srivastava is President, Centre for Applied Research in Governance, Delhi.

THE GIST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा है।

भारत के संविधान में राज्यों के निर्माण के लिए तीन प्रक्रियाएँ निहित हैं - प्रवेश, स्थापना और निर्माण।

द्विसंसीय शासन प्रणाली होने के बावजूद, इसमें 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि 'संघ' स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस अनूठी विशेषता के पीछे का उद्देश्य भारत के संघीय चरित्र और एकात्मक भावना को सुनिश्चित करना है।

THE GIST

यद्यपि ओर्का को सामाजिक प्राणी माना जाता है, फिर भी वे मनुष्यों के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं।

टीम जिन 34 मामलों को अंतिम रूप देने में सफल रही, उनमें से 33 मामलों में ओर्का ने मानव प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की, उसके बाद उन्होंने अपने शिकार को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने शिकार को छोड़ दिया।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किलर ढेल शायद बस खेल के बीच बातचीत बढ़ावा देती है, ओर्का ने अपने व्यवहार को

From Page One

‘भारत, चीन सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध’

श्री मिसरी ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने संतुलित द्विपक्षीय व्यापार पर विचारों का आदान-प्रदान किया और माना कि उनकी अर्थव्यवस्थाएँ विश्व व्यापार को स्थिर कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि वे व्यापार धाटे को कम करते हुए व्यापार और निवेश संबंधों को सुगम बनाने पर सहमत हुए। विदेश सचिव ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और श्री मोदी ने श्री शी से कहा कि बढ़ता व्यापार चीन के प्रति दुनिया की धारणा में बदलाव लाने में योगदान देगा।

यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ युद्धों की पृष्ठभूमि में हुई, लेकिन श्री मोदी ने ज़रा देकर कहा कि भारत और चीन के संबंधों को "तीसरे देश के चश्मे" से नहीं देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रणनीतिक स्वायत्ता चाहते हैं, वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि वे बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर अपने साझा आधार का विस्तार करेंगे।

'सकारात्मक गति'
"राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक सार्थक बैठक हुई... हमने कजान [रूस में, अक्टूबर 2024 में] में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक गति की समीक्षा की," श्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा। उन्होंने आगे कहा, "हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमत हुए और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी एकजुटता पर आधारित सहयोग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दीहाराई।"

श्री शी ने कहा कि दोनों देशों को शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और सीमा मुद्दे को अपने समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि "डैगन और हाथी का सहयोगी पा-दे-दो दोनों देशों के लिए सही विकल्प होना चाहिए।" श्री शी ने कहा कि चीन और भारत प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोग साझेदार हैं, और श्री मोटी ने भी यही भावना दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने दोहराया कि दोनों देश "विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने स्यामार के विरोध जनरल मिन आग हून से भी मुलाकात की और संकटग्रस्त देश की विकासात्मक आवश्यकताओं में सहयोग के लिए भारत की तपतरा दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने कहा कि भारत अपनी 'पड़ोसी पहले', 'एक ईस्ट' और हिंदू-प्रशांत नीतियों के तहत स्यामार के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है।

श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि म्यामार में आगामी चुनाव सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत म्यामार के नेतृत्व वाली और म्यामार के स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत और परामर्श ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

तिआनाजन धरणपत्र के सम्बन्ध का सकृत प्रधानमंत्री ने रविवार रात श्री शी और उनकी पत्नी पेंग लियुआन द्वारा आयोजित एक भोज समारोह में भी भाग लिया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति ल्वादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ सहित अन्य एससीओ नेता शामिल थे।

विदेश मत्रालय न कहा कि श्रा मादा न माजूदा शिखर सम्मलन की अध्यक्षता चीन को सौंपे जाने के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इससे यह संकेत मिलता है कि दस सदस्यीय समूह के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के बाद सोमवार को हस्ताक्षरित और जारी किए जाने वाले तियानजिन घोषणापत्र पर उनके द्वारा कोई आपत्ति उठाए जाने की संभावना नहीं है।

श्री मार्दों ने श्री शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि श्री शी ने उस समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपे जाने के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

प्रदान करना याहा कुछ भी बात को जासू रखना चाहिए। समिति की सदस्य के व्यक्ति से भी मुलाकात की और “दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को साकार करना” के लिए समर्थन मांगा। मंत्रालय ने कहा कि श्री कैर्न्स ने दिपश्रीय भाद्रन-पटन बढ़ाने की

**प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग से कहा,
दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं**

रविवार की बैठक के बाद तियानजिन में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में श्री मिसरी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपनी समझ को बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि यह एक ऐसा संकट है जिसके शिकार चीन और भारत दोनों रहे हैं, और भारत अभी भी इस समस्या से जु़झ रहा है, और उन्होंने इस विशेष मुद्दे पर चीन का समर्थन मांगा।"

पाकिस्तान को चीनी सहायता पर कोई टिप्पणी नहीं
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, श्री मिसरी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद की प्राथमिकता बताया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की चीन के समर्थन से जुड़े एक प्रश्न को टालते हुए उन्होंने कहा, "श्री मोदी ने इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि यह भारत और चीन दोनों को प्रभावित करने वाला विषय है और हमस्तिप्रयग महत्वपूर्ण है कि हम सीमा पार आतंकवाद से

निपटने के लिए एक-दूसरे के प्रति समझा और समर्थन बढ़ाए।" श्री मिसरी ने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के मुद्दे पर भारत को शंघाई सहयोग संगठन में चीन की "समझा और सहयोग" प्राप्त हआ है। भारत को उम्मीद है कि सोमवार को जारी होने वाले एससौओ के संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का ज़ोरदार ज़िक्र होगा।

बदलता रुख

पूछे जाने पर, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि श्री मिसरी चीन के खिलाफ आतंकवाद की किन विशिष्ट घटनाओं का ज़िक्र कर रहे थे। पिछले एक दशक से, चीन देश में हिंसा के लिए तिक्कती और उड़िगर समूहों और पाकिस्तान में चीनी कामगारों पर हमलों के लिए बल्चून समूहों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। हालांकि, भारत ने पहले इन दावों का समर्थन नहीं किया है, और

बदलता रुख

पूछे जाने पर, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि श्री मिसरी चीन के खिलाफ आतंकवाद की किन विशिष्ट घटनाओं का ज़िक्र कर रहे थे। पिछले एक दशक से, चीन देश में हिंसा के लिए तिक्कती और उड़गा समूहों और पाकिस्तान में चीनी कामगारों पर हमलों के लिए बलूच समूहों को ज़िम्मेदार ठहराता रहा है। हालांकि, भारत ने पहले इन दावों का समर्थन नहीं किया है, और

News

श्री परबत ने बताया, "समीक्षा समिति द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद, यह सीबीडीटी के कर नीति एवं विधान [टीपीएल] प्रभाग के पास आया।"

MONEYWISE

क्रिएटो को डिकोड करना

Vaishali R. Venkat

पिछले हफ्ते, हमने ब्लॉकचेन, जो क्रिप्टोकरेंसी का इंजन है, की बुनियादी बातों पर चर्चा की। अब, हम शृंखला की अगली पत्र पर चर्चा है। चैंके ब्लॉकचेन में ब्लॉक एक बाद एक बाद जा सकते हैं। इसलिए अगला ताकिंक प्रश्न यह है कि ब्लॉक कोने जोड़ता है और ब्लॉक कैसे जोड़ जाते हैं।

किसी लेनदेन को किसी ब्लॉक में तभी जोड़ा जा सकता है जब कोई उसे सत्यापित करा लेकिन कौन सत्यापित करता है, यह एक बड़ा सवाल है। बैंकों या वित्तीय संस्थाओं जैसे केंद्रीकृत संस्थानों में, बैंक अधिकारी प्रत्येक लेनदेन का सत्यापन करते हैं। लेकिन किसी भी लेनदेन एक विकेन्ट्रोकृत नेटवर्क पर संचालित होते हैं और ब्लॉकचेन के सहमति तंत्र के आधार पर, माहनंग या सत्यापनकर्ता नामक प्रतिभागियों द्वारा सत्यापित किए जाते हैं।

ब्लॉकचेन को विकेन्ट्रीकृत होते हैं, जिनमें कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता। इसलिए, नेटवर्क को एक ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा सभी प्रतिभागी बहीखाते की "सत्यता" पर, यानी लेनदेन की वैधता पर, एक समझौते पर पहुंचे। इसे सहमति तंत्र कहा जाता है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉकचेन नेटवर्क यह तय करता है कि कौन से लेनदेन मान्य हैं और उन्हें जोड़ा जा सकता है।

क्रिएटो में, ऐसे कई सहमति तंत्र होते हैं। हालांकि, सबसे लोकप्रिय हैं प्रूफ ऑफ वर्क (PoW) और प्रूफ ऑफ स्टेक (PoS)।

PoW ब्लॉकचेन में, माइनर्स नोइस नामक शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग करके जटिल पहेलियों को सुलझाने के लिए एक-दूसरे से प्रतिपथ्या करते हैं। माइनिंग सुटोक की तरह है, लेकिन काफी जटिल और पेनीदा पेहली है। जो भी इस प्रैली में सफल होता है, उसे पूर्ण मिलता है और वह नया ब्लॉक जोड़ता है। माइनिंग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कंप्यूटरी शक्ति की आवश्यकता होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लेन-देन सत्यापित हो। केवल वैध लेन-देन ही ब्लॉक में जोड़ जाएं और ब्लॉकचेन सुरक्षित रहे। PoS सिस्टम में, सत्यापनकर्ताओं का चयन इस आधार पर किया जाता है कि वे कितने सिवक "दांव" पर लगाते हैं। स्टेकिंग वैसे को तिजोरी में रखने जैसा है। आप जितना अधिक दाव लगाते हैं, उने की संभावना उत्तमी ही अधिक होती है। हालांकि व्यवहार से शुक्र या नए सिवक के मिलते हैं, वे बेर्टमारी से दाव पर लगाए गए सिवक खो जाते हैं। ये दोनों तरह यह सुनिश्चित करते हैं कि खेखाई वाले लेन-देन रोक जाएँ और नेटवर्क सुरक्षित रहे। इसके अलावा, ये प्रतिभागियों को प्रोत्साहित भी करते हैं।

क्या जाँचे

"तो, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से पहले आपको क्या जाँचना चाहिए?"

केवल PoW या PoS तंत्र पर विचार करना पर्याप्त नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। इनमें नेटवर्क सुरक्षा और संरक्षा शामिल है, जैसे कि सक्रिय नोइस लाना एक मजबूत और विकेन्ट्रोलीन नेटवर्क के लिए आवश्यक है। इसके बाद, लेन-देन की गति और शुल्क, ब्लॉक के दोनों सीधे तर पर कॉइन की उपयोगीता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद, बाजार की प्रतिष्ठा, यानी कॉइन का इतिहास, सुमुद्रा और विकास परियोजनाओं से बचने में मदद मिलती है।

इसके बाद, क्या कॉइन वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करता है और इसे अपनाया जा सकता है। केवल व्यावहारिक अनुयोगों वाले कॉइन ही भूमिका नहीं रखते हैं। सबसे बढ़कर, क्रिएटो की कीमतों में बेहतर शुल्क-चाहावे के साथ कॉइन की अस्थिरता पर विचार करें। इन पहलुओं पर विचार करने से, लोकों के सत्यापन, सत्यापन और अन्वेषकों को संचित निर्णय लेने और अतिरिक्त परियोजनाओं से बचने में मदद मिलती है।

मुद्रा के प्रकार
क्रिएटोकरेंसी कई प्रकार की होती है। बिटकॉइन पहला और सबसे प्रसिद्ध है। ऐसेरिका और सोलाना जैसे अंलटकॉइन स्मार्ट कॉर्नेक्ट के अनुयोग प्रदान करते हैं। USDT या USDC जैसे स्थिरकॉइन वास्तविक संपत्तियों से जुड़े होते हैं। उपर्योगी का शासन के लिए टोकन; मीम कॉइन, जो प्रचार और सम्बन्ध द्वारा संचालित होते हैं और कृष्ण अन्य कॉइन वित्त, आपूर्ति श्रृंखला, गेमिंग आदि जैसी वास्तविक उपयोगी की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं।

दीर्घकालिक निवेश के लिए, ऐसे कॉइन जो वास्तविक उपयोगी की समस्याओं का समाधान करते हैं, या जिनमें व्यावहारिक अनुयोग हैं और जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है, आसानी पर प्रचार-आधारित कॉइन से अधिक मूल्यवान होते हैं।

(तेज़ख एनआईएसएम और क्रिप्टोल-प्रमाणित वेल्य मैनेजर हैं और एनआईएसएम के रिसर्च एनालिस्ट माइक्रॉल में प्रमाणित हैं)



ILLUSTRATION: SAINATH B.

अनिवासी भारतीय चिकित्सा पर्यटन के लिए भारत को क्यों चुन रहे हैं?

जब लोग मेडिकल ट्रूरिजम के बारे में सोचते हैं, तो वे अक्सर सामर्थ्य और गुणवत्ता के बीच समझौता करने की कल्पना करते हैं। भारत ने यह साबित करके समीकरण को फिर से लिख दिया है कि किसी को भी किसी भी चीज़ से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।

HEALTH ECONOMICS

Siddharth Singhal

स्वास्थ्य सेवा से जुड़े फैसले, शायद किसी भी अन्य फैसले से ज्यादा, भरोसे, पहुंच और ऐसे कीमत के जटिल समीकरण को दर्शाते हैं। इसमें अनिवासी भारतीयों के लिए भोग्योलिक दूरी का कारक भी जोड़ दें, तो यह फैसला और भी जटिल हो जाता है। लालों अनिवासी भारतीयों के लिए, यह फैसला अब विदेशों में बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत और भारत में समय पर, उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल के आधार की वास्तविकताओं से प्रभावित होता है।

जब लोग चिकित्सा पर्यटन के बारे में सोचते हैं, तो वे अक्सर सामर्थ्य और गुणवत्ता के बीच सुरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में हदय बाईपास सर्जरी की लागत \$5,000-\$8,000 है, जबकि अमेरिका में \$10,000-\$15,000 है। अमेरिका में घुटने के प्रत्यारोपण की लागत \$50,000 डॉलर तक है, जबकि भारत में 4,000-\$6,000 डॉलर है।

भारत को चिकित्सा पर्यटन के लिए, इसका मतलब है बिना किसी वित्तीय दबाव के व्यापक सुरक्षा प्राप्त करना।

अनिवासी भारतीयों के लिए, इसका मतलब है बिना किसी वित्तीय दबाव के व्यापक सुरक्षा प्राप्त करना।

वित्तीय तंत्र ग्रामीण दिलचस्प बात है कि चिकित्सा पर्यटन के लाभ अब केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हैं।

वास्तव में, लाभग्राही अधिक अनिवासी स्वास्थ्य बीमा दावे अब टियर-3

शहरों और कर्जों से आते हैं। यह एक नेटवर्क के लाभ अब केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है।

वास्तव में, लाभग्राही अधिक अनिवासी स्वास्थ्य बीमा दावे अब टियर-3

शहरों और कर्जों से आते हैं। यह एक नेटवर्क के लाभ अब केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है।

जिससे यह बहुत अधिक अनिवासी भारतीय दूर से ही पहुंचता है और उन जायिमों से खुद को बचा लेते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है कि वे उनके सामाने आ सकते हैं।

पॉलिसी का जोर, डिजिटल प्रचार

हील इन इंडिया जैसी सरकारी

पहल और डिजिटल-फर्स्ट प्लेटफॉर्म

के विवास ने इस प्रक्रिया को और

सरल बना दिया है। अनिवासी

भारतीय दूर से ही पॉलिसियों की

खोज, तुलना और खरीद का सकते हैं।

अस्पतालों में केशलेस दावों ने इस दूरी को कम कर दिया है,

जिससे हजारों मील दूर होने पर भी

निवासी पहुंच सुनिश्चित हुई है।

डिजिटल पहुंच की स्विंग और

प्रीमियम की किफायती कीमत ने

बीमा को चिकित्सा पर्यटन की

कहानी का एक स्वाभाविक विस्तार बना दिया है।

भारत में इलाज चुनने से होने वाली

बचत सिर्फ़ अस्पताल के बिल के

आंकड़े नहीं हैं। ये सीधे तौर पर

प्रभावित करते हैं। पहले से ही

बैंक, बच्चों की शिक्षा और

सेवानिवृत्ति के लक्ष्यों को संतुलित

कर रहे अनिवासी भारतीयों के

लिए, यह अंतर जीवन बदल देने

वाला ही सकता है।

SCIENCE

आंकड़े बताते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप के आसपास समुद्र का जलस्तर अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ रहा है

प्रवाल सूक्ष्म-परतें डिस्क के आकार की बस्तियाँ होती हैं जिनकी ऊपर की ओर वृद्धि निम्नतम ज्वार की ऊँचाई के कारण सीमित हो जाती है। परिणामस्वरूप, सूक्ष्म-परतें की ऊपरी सतह समय के साथ क्षेत्र के निम्नतम जल स्तर को बारीकी से दर्शाती है। ये प्रवाल दशकों या सदियों तक जीवित रह सकते हैं, और बदलते समुद्र स्तर के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ते हैं।

Neelanjana Rai

समुद्र का बढ़ता स्तर ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख परिणाम है, जिसके निचले तटीय क्षेत्रों पर कई प्रभाव पड़ रहे हैं। प्रवाल भित्तियाँ, जो अपने पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, समुद्र तल में उत्तर-चाढ़ाव के प्रति भी विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। जब समुद्र तल बढ़ता है, तो सूर्य का प्रकाश उस प्रवाल भित्ति तक पहुँचने के लिए पानी में प्रवेश नहीं कर पाता जहाँ वह पहले पहुँच सकता था। इससे प्रवाल विरेन्जन हो सकता है।

ज्वार-भाटा के पैटर्न में बदलाव और तटीय कटाव में वृद्धि, रीफ परिस्थितिकी तंत्र पर पर और अधिक दबाव डाल सकती है, जो पहले से ही गर्म पानी और समुद्री अम्लाकरण का दंश झेल रहा है।

महत्वपूर्ण अंतराल

महासागरीय बेसिनों में समुद्र तल में वृद्धि की निगरानी एक सतत वैज्ञानिक प्राथमिकता रही है। हिंद महासागर में, पांचवीं विंद महासागर (1985-1994) में उत्तरांतरिक बिंद महासागर वैश्विक वायुमंडल कार्यक्रम की दौरान दैर्घकालिक प्रयास शुरू हुए। बाद में इन प्रयासों को वैश्विक समुद्र तल अंतरालक प्रणाली में शामिल कर लिया गया, जो इस क्षेत्र में अनुसंधान को समर्थन प्रदान करती रही है।

भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, हिंद महासागर का जलस्तर औसतन लगभग 3.3 मिमी/वर्ष की दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। महासागर में औसत से अधिक तापमान वृद्धि भी हो रही है, जिससे महासागरीय गतिशीलता और वायुमंडलीय परिस्वरण में परिवर्तन बढ़ सकते हैं, जो बदले में प्रवाल विरेन्जन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं।

इसके बावजूद, समुद्र-स्तर के रिकॉर्ड में अभी भी काफी अंतराल है, खासकर मध्य उत्तरांतरिक हिंद महासागर में। एक नए अध्ययन ने अब इस क्षेत्र में समुद्र-स्तर के रिकॉर्ड को ऊपर बढ़ा दिया है, जो दर्शाता है कि यहाँ जल स्तर 1950 के दशक के अंत में ही बढ़ना शुरू हो गया होगा, जो पारपरिक ज्वार मापक रिकॉर्ड द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से काफी पहले का है।

अम्लसाध्य सर्वेक्षण

इस अध्ययन में, सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल केंच के नेतृत्व में एक टीम ने नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर प्रवाल सूक्ष्म-एटोल का अध्ययन किया, जो एक प्राकृतिक सर्वेक्षण है जिसके बारे में उन्होंने पाया कि यह उच्च-रिजन्सल्यूशन, दीर्घकालिक समुद्र-स्तर रिकॉर्ड प्रदान कर सकती है।

प्रवाल सूक्ष्म-परतें डिस्क के आकार की बस्तियाँ होती हैं जो निम्नतम ज्वार की ऊँचाई के कारण ऊपर की ओर बढ़ने में बाधा पड़ने पर बगल में बढ़ती हैं। इस सीमा के कारण, सूक्ष्म-परतें की ऊपरी सतह समय के साथ उस क्षेत्र के निम्नतम जल स्तर को बारीकी से दर्शाती है। ये प्रवाल दशकों या सदियों तक जीवित रह सकते हैं, और बदलते समुद्र स्तर के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ते हैं।



रियनियन द्वीप के पास पोरीटेस ल्यूटिया माइक्रोएटोल, 2009. फ़िलिप बोर्जन (CC BY-SA)

यह अध्ययन मालदीव के हुवाधू एटोल में स्थित एक शीक्षणीय मुदुतिगाल पर किया गया था। टीम ने एक पोरीटेस माइक्रोएटोल का अध्ययन किया, इसकी संरचना को मापा और नमूने लिए ताकि 1930 से 2019 तक के समुद्र-स्तर के इतिहास का पता लगाया जा सके।

शोधकर्ताओं ने प्रवाल के बाहरी की किनारे और सतह की ऊँचाई का बारीकी से सर्वेक्षण किया। फिर उन्होंने बाहरी किनारे से माइक्रोएटोल के केंद्र तक एक स्लैब काटा और स्लैब का एक्स-रेटर करके वृद्धि पट्टियों दिखाई - बिल्कुल वृद्धों के छल्लों की तरह। इन पट्टियों ने प्रवाल के विकास की एक स्टीक समयरेखा प्रदान की, जिसमें यह ही शामिल था कि यह कब समुद्र तल तक पहुँचा और कब मरा। टीम ने समुद्र तल के सापेक्ष इसकी ऐतिहासिक ऊँचाई निर्धारित करने के लिए यूरेनियम-थोरियम डेटिंग का भी उपयोग किया।

धारणा को चुनौती दी गई

टीम द्वारा इस तरह से पुनर्निर्मित किए गए आंकड़ों से पता चला कि 90 वर्षों की अवधि में समुद्र का स्तर लगभग 0.3 मीटर बढ़ा है। समय के साथ वृद्धि की दर में उल्लेखीय वृद्धि हुई: 1930-1959 में 1.184 मिमी/वर्ष, 1960-1992 में 2.76-4.12 मिमी/वर्ष, और 1990-2019 में 3.91-4.87 मिमी/वर्ष।

साथ ही, टीम के अनुसार, इस क्षेत्र में समुद्र-स्तर में वृद्धि 1950 के दशक के अंत में शुरू हो गई, जो पहले के अनुमान से दशाओं पहले थी।

इसका अर्थ है कि मालदीव, लक्षद्वीप और चांगोंस द्वीपसमूह कम से कम 60 वर्षों से महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह डेटा जलवायु परिवर्तन और अनूकूलन कार्य में इस आम धारणा को चुनौती देता है कि समुद्र-स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि का इतिहासिक कार्य है।

श्री केंच के अनुसार, हालांकि प्रवाल सूक्ष्म-परतें ज्वारमात्रीय और चांगोंस द्वीपसमूह कम से कम 60 वर्षों से महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही है।

यह एक आवश्यक अंतराल है जिसके बाद वृद्धि नहीं है, और पिछली आधी सदी में कुल वृद्धि 30-40 सेमी रही ह